भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2215
20 दिसंबर 2022 ,को उत्तर दिए जाने के लिए

मत्स्यपालन और गाय पालन

2215. श्री रामदास तडस:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मत्स्यपालन और गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है अथवा बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में मत्स्यपालन की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य में कोई योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) से (ग): गाय पालन सहित मत्स्यपालन और पशुपालन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के प्रयासों में संवर्धन और अनुपूर्ति करने के लिए मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार महाराष्ट्र सहित, देश भर में विभिन्न योजनाओं को लागू करता है जैसे (i) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), (ii) मात्स्यिकी और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ), (iii) डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीडीडी), (iv) डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ़), (v) डेयरी गतिविधियों में लगे हुए डेयरी सहकारी और किसान उत्पादक संगठनों (एफ़पीओ) को सहायता देना, (vi) डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस), (vii) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ़) आदि ।

मत्स्यपालन विभाग ने 2020-21 में पीएमएमएसवाई की शुरुआत से अब तक महाराष्ट्र राज्य में मत्स्य पालन और जल कृषि के विकास के लिए 607.73 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय पर परियोजना प्रस्ताव मंजूरी किए हैं जिसमें केंद्रीय हिस्सेदारी 239.57 करोड़ रुपये है । पीएमएमएसवाई में अन्य बातों के साथ-साथ स्वीकृत की गई मुख्य गतिविधियों में अंतर्देशीय और खारे पानी दोनों में इनपुट सहायता सहित जल कृषि गतिविधियों के लिए तालाबों का निर्माण, जलाशयों और खुले जल निकायों में मछली पालन के लिए केजों / पेन की स्थापना, जलाशयों का एकीकृत विकास, हैचरी की स्थापना, बीज पालन क्षेत्र का निर्माण, समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देना,

समुद्री केज में कल्चर और बि-वाल्व कल्चर, री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस) की स्थापना, फिश फीड मिल की स्थापना, पोस्ट हवेस्ट इनफ्रास्ट्रक्चर जैसे आईस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, आईस प्लांट कम कोल्ड स्टोरेज, मत्स्य परिवहन और विपणन इनफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेफ्रिजरेटेड और इंसुलेटेड वाहन, दो / तीन पहिया वाहनों के साथ आइस-बॉक्स, लाइव फिश वेंडिंग यूनिट, फिश कियोस्क आदि शामिल है ।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग दिसंबर 2014 से देशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन कार्यान्वित कर रहा है । दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने और देश के ग्रामीण किसानों के लिए डेयरी को अधिक लाभकारी बनाने के लिए दुग्ध उत्पादन और गोवंश की उत्पादक क्षमता बढ़ाने में यह योजना महत्वपूर्ण है। यह योजना 2400 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ 2021-22 से 2025-26 तक विभाग की संशोधित और पुनर्गठित योजना के तहत जारी है । इस योजना का उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि करना और डेयरी व्यवसाय में लगे 80 मिलियन किसानों को, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाना है।

*****